REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF)
VOLUME - 7 | ISSUE - 6 | MARCH - 2018

शिक्षक–शिक्षा में गुणवत्ता के मुद्दे

Manoj Kumar
Research Scholar , School Of Education , Rani Durgavati Vishwavidyalaya, (Jabalpur)

प्रस्तावना

स्वतंत्रता प्रप्ति के समय से ही भारत सरकार ने देश की परम्पराओं एवं मान्यताओं तथा आधुनिक समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान रख कर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने का प्रयास किया है। इस दिशा में कुछ ठोस कदम भी उठाए गए है, पर शिक्षा प्रणाली का विकास समय की आवश्यकताओं के अनुरुप नही हुआ है। अध्यापक शिक्षा की सामान्य स्थिति राष्ट्र के लिए भारी चिन्ता का विषय है। शिक्षा की संख्यात्मक वृद्धि तो हुई है पर गुणात्मक नही। अध्यापक शिक्षा की दशा सोचनीय क्योकि आज उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले हमारे विद्यार्थियों के सामने सक्रिय उद्देश्य नहीं है।

वर्त्तमान ज्ञान प्रेमी समाज में उच्च शिक्षा की बड़ी भूमिका होती है। राष्ट्रीय संपदा कोसमृद्ध करने में यह बड़ा योगदान करती है। आर्थिक समृद्धि और मानवीय पूंजी के बीचसंबंध की स्थापना में इसका कार्यकारी अवदान होता है। मानवीय पूंजी के विकास के हीअनुपात में राष्ट्रीय पूंजी और आय में वृद्धि होती है। अतएव मानवीय ज्ञान और कुशलताओंके परिप्रेक्ष्य में यदि धन और सुविधओं का निवेश किया जाएगा तो निश्चय ही इनमें वृद्धिहोगी। शैक्षिक अर्थशास्त्रियों ने प्रयोगों के आधर पर ऐसे निष्कर्ष निकाले हैं कि 21वींसदी के शुभागमन ने इस तथ्य को और भी मुखरित कर दिया है। मात्रा गुणसंवाही सीखनेकी संस्थाएँ ही विश्व नेतृत्व की क्षमता से राष्ट्र–युवाओं को संयोजित कर सकती हैं। इसगुणवत्ता की दशा को मूर्त रूप प्रदान करने के लिये उच्च शिक्षा के संस्थानों की आंतरिकगतिकी (The Internal Dynamics)अभिनवतापूर्वक समुन्नत करना होगा और व्यवस्थामें युगापेक्षी परिवर्तन लाना होगा।

अध्यापक शिक्षा की वर्तमान मुद्दे

नवज्ञान और अधिगम के क्षेत्रा में त्वरित और क्रांतिकारी विकास के कारण आज काअध्यापक –शिक्षा जगत संक्रमण की परिस्थिति से गुजर रहा है। यहां नित्य नई चुनौतियांउभर रही हैं अनेकानेक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक कारण इन्हें और भी बढ़ा रहे हैं। प्रत्येक स्तर पर अध्यापक शिक्षा का मूलभूत लक्ष्य यथापेक्षा पूरित नहीं हो पा रहा है। इसीकारणवश अध्यापक शिक्षा न तो उत्तम अध्यापक एवं अध्यापिका की तैयारी को सुनिश्चित कर पा रही है और न ही उनमें उच्च स्तरीय गुणात्मकता को समावेशित कर पा रही है। अध्यापक श्रेष्ठ निर्देशकर्त्ता के रूप में उभर नहीं पा रहे हैं। जिससे अध्यापक शिक्षा के संकल्पित निहितार्थ पूरे नहीं हो पा रहे हैं। फलस्वरूप आज की अध्यापक शिक्षा अनेकानेक समस्याओं से जूझ रही ळें

प्रवेशपरकमुद्दे

वर्तमान देश प्रदेश में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों में प्रवेश, एक बड़ी समस्या बना हुआ है। विश्वव्यापी 'सर्व–शिक्षा अभियान' के तहत इन वर्षों में पूरे देश में प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय तेजी से बड़ी संख्या में खोले गए हैं और खोले जा रहे हैं इस कारण से बड़ी संख्या में अध्यापकों की आवश्यकता आ पड़ी है। इस आवश्यकता पूर्ति के आशय से पूरे प्रदेश में, देश में बड़ी संख्या में अध्यापकों की आवश्यकता आ पड़ी है। इस आवश्यकता पूर्ति के आशय से पूरे प्रदेश में, देश में बड़ी संख्या में अध्यापक –प्रशिक्षण पाठ्यक्रम खोले गए हैं जिनमें बी.एड्., बी.पी.एड्. , डी.एल्.एड् आदि कक्षाओं में प्रशिक्षणार्थियों की कई गुना सीटें बढ़ी हैं। राज्य सरकारें और विश्वविद्यालय स्वयं इस दिशा में सक्रियता बरत रहे हैं। पर इन विभिन्न स्तरों पर प्रवेशार्थियों का चयन करते समय जिन मापदण्डों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, प्रायः उनका अनुपालन कठिनाई से हो रहा है।

प्रवेश हेतु चयन के लिये जहाँ पहले उपलब्धिगत सूचकांक को महत्त्व दिया जाता था वहाँ आज अधिकांशतः उसके स्थान पर प्रवेश–परीक्षा को महत्त्व दिया जा रहा है।प्रश्नपत्रों में प्रायः सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न रखे जा रहे हैं। विषयगत ज्ञानात्मक स्तरीय प्रश्नों को उतना महत्त्व नहीं दिया जा रहा है। फलतः यह परीक्षण यथारूपेण पूर्ण नहीं दिखायी पड़ता। इन परीक्षणों में भाषागत या अभिव्यक्तिपरक योग्यताओं के परिज्ञान हेतु यथेष्ट प्रयास नहीं दिखायी पड़ता। इसी भाँति इनमें शिक्षण–अभिवृत्ति, रुचि, अभिक्षमता आदि के सम्यक् ज्ञान हेतु कोई समीचीन प्रयास नहीं दिखायी पड़ता एवं विविध विद्यालय अध्यापन–विषयों में योग्यता–प्रशिक्षण हेतु समुचित प्रश्नों का निर्माण प्रवेश–परीक्षा प्रश्नपत्रों में प्रायः नहीं किया जाता तथा सामान्य मानसिक योग्यता एवं उसके आयामों को जानने के लिये किसी मानवीकृत परीक्षण का प्रयोग करना जरुरी नहीं माना जाता है। परिणामस्वरूपप्रवेश–परीक्षा मात्रा एक दिखावा बनकर रह गयी है।

इतना ही नहीं सभी राज्य के विश्वविद्यालयों के अध्यापक–शिक्षा पाठ्यक्रमों में N.C.T.E.के दिशा निर्देशों के बावजूद काफी भिन्नता पायी जाती है। प्रशिक्षण विभागों,संस्थानों में प्रवेश की एकाधिक कोटियाँ भी व्यवहार में लागू हैं। प्रदेश में सम्प्रति **85%** सीटें सीधे विश्वविद्यालय की सूची से भरी जाती हैं जबकि **15%** सीटें प्रबन्धकीयद व्यवस्था के द्वारा भरी जाती हैं और जिनके नियमों में वर्ष प्रतिवर्ष भिन्नता दिखायी पड़ती है। इन दशाओं–परिस्थितियों के चलते प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रवेश अनेकानेक समस्याओं से घिरा दिखायी पड़ता है जिनका समाधान दुश्कर प्रतीत हो रहा है।

प्रशासनिकमुद्दे

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्रो में राज्य, शासन और विश्वविद्यालययों का नियन्त्रण कम है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने की अनुमति 'राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद' देती है। इससे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और नए प्रशिक्षण–संस्थान खोलना काफी कठिन हो गया है। तब भी देश के विभिन्न राज्यों में लगभग पाँच वर्षों में अच्छी संख्या में स्व–वित्तपोषित प्रशिक्षण के विभाग – संस्थान पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किए हैं। प्रायः संस्थानों को प्रवेशार्थ एक सौ सीटें दी गयी हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश चयन हेतु प्रवेश परीक्षाएँ संचालित की जा रही हैं तथापि विश्वविद्यालयों को इन परीक्षाओं के आयोजन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहीं माफिया गिरोह प्रवेश प्रक्रिया को बाधित कर रहा है तो कहीं अन्यान्य अभिकरण और तत्त्व प्रवेश प्रक्रिया की शुद्धता को प्रदूषित कर रहे हैं। इतना ही नहीं कहीं–कहीं तो परीक्षा आयोजक तन्त्र ही इनमें प्रदूषण फैलाता दिखता है। ऐसी दशा में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ चयन, शुद्धता के नाम पर गम्भीरता से प्रश्नचिन्ह लग जाता है। स्व–वित्तपोषित कॉलेजों की अपनी अनेक समस्याएँ हैं। उन्हें एक तो सुयोग्य अध्यापक नहीं मिल पा रहे हैं और यदि मिलते भी हैं तो वे उन्हें उचित वेतन नहीं दे पा रहा है। इन महाविद्यालयों के अधिकांश प्रबन्धतन्त्र तो इस पाठ्यक्रम के द्वारा महाविद्यालय और निजी कोषों को भरने की प्रवृत्ति से ग्रस्त दिखते हैं। इससे शिक्षण और प्रशिक्षण का स्तर गिरता जा रहा है। राज्य शासन, विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ये सभी मिलकर भी वांछित प्रतिमानों का अनुरक्षण नहीं कर पा रही हैं। स्थिति स्पष्ट है कि संस्थाएँ पाठ्यक्रमों की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। प्रशिक्षणपरक बी.एड., बी.पी.एड. आदि उपाधि आवश्यक होते हुए भी मखौल का विषय बन गयी हैं। प्रवेश, शिक्षण, प्रशिक्षण,शोध तथा परीक्षण इनके सारे प्रतिमान गिरते जा रहे हैं।

पाठ्यक्रम संबंधी मुद्दे

अध्यापक–शिक्षा का प्रचलित पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर पर सर्वत्रा प्रायः एक वर्ष का है। जिसमें अवकाश एवं प्रवेश अवधि को छोड़कर लगभग दो सौ दिन का समय शेष रह जाता है। यह प्रचलित पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है। इसी कारणवश राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने इस अवधि को दो वर्षीय करने की सिफारिश की थी वर्तमान में 2015 से इसे लागू कर दिया गया है। इंटर्नशिप को अनिवार्य बनाए जाने की दिशा में यह और भी समीचीन प्रतीत होती है किन्तु अधिकांश संस्थाओं ने इसे व्यावहारिक करने में अपनी अक्षमता प्रकट की है।

इसी भाँति पाठ्यक्रम में कई ऐसे सैद्धांतिक प्रश्न पत्र निर्धरित मिलते हैं जिनका व्यावहारिक शिक्षण–प्रशिक्षण से सीधा संबंध नहीं दिखायी पड़ता। पाठ्यक्रम में विस्तार के कारण यह लगभग **40%** का समय ले लेता है। फल यह होता है कि प्रायोगिक कार्य तथा शिक्षण अभ्यास आदि के लिये शेष **30%** समय ही बच पाता है। इससे पाठ्यक्रम में व्यावहारिक एवं प्रायोगिक पक्ष प्रायः अपेक्षित बना रहता है। इतना ही नहीं अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में तादात्म्य और सह–सम्बन्ध की कमी भी प्रायः देखने को मिलती है। देखा जा रहा है कि शिक्षण कला, तकनीकी एवं मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न पत्रों को शिक्षा के सिद्धांत, शिक्षा का मनोविज्ञान तथा शिक्षा का इतिहास आदि की तुलना में कम महत्त्व दिया जाता है। यह भी देखा जा रहा है कि इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्र सहभागिता मूलक तकनीकों को कम महत्त्व दिया जा रहा है, पाठ्यक्रम विश्लेषण तो प्रायः किया ही नहीं जाता। प्रस्तुतिकरण योजना निर्माण के लिये कोई ठोस प्रयत्न किये जाते नहीं दिखाई पड़ते। अधिगम के लिए मात्रा व्याख्यान विधि का सहारा लिया जाता है। परीक्षण पूर्णतः सैद्धांतिक पाठ्यक्रम अधारित है, जिसे समीचीन और यथेष्ट नहीं कहा जा सकता। इसी भाँति प्रायः देखा गया है कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में शिक्षण अभ्यास को समुचित महत्त्व नहीं दिया जाता है। इससे संबंधित अंशों सूक्ष्म–शिक्षण, लघु–शिक्षण, अनुरूपित–शिक्षण आदि पाठ्य प्रकरणों पर अनेक संस्थाओं में यथेष्ट सैद्धांतिक पाठ्यक्रम आधरित हैं, जबकि यह व्यावहारिक शिक्षण अभ्यास की दृष्टि से परमावश्यक है। ऐसे ही अधिकांश प्रशिक्षण संस्थानों में छात्र–छात्राओं द्वारा शिक्षण अभ्यास की औपचारिकता निभायी जाती है जो कि नितांत चिन्तनीय है।

इस प्रकार यह सहज कल्पनीय है कि इन दिनों हमारे प्रशिक्षण संस्थान पूर्ण और यथेष्ट आधुनिक पाठ्यक्रम का व्यावहारिक अनुगमन नहीं कर पा रहे हैं, यद्यपि औपचारिक रूप से इन पाठ्यक्रमों को प्रायः आधुनिक अद्यतन अवश्य बनाया गया है।

शिक्षण अभ्यास से संबंधित मुद्दे

वर्तमान अध्यापक–शिक्षा कार्यक्रम का यह एक बड़ा अपेक्षित पक्ष है। अधिकांश प्रशिक्षण संस्थानों में इन दिनों न तो यथेष्ट अध्यापकीय निरीक्षण–पर्यवेक्षण की व्यवस्था दिखाईपड़ती है न ही प्रशिक्षणार्थियों को इतना समय दिया जाता है कि वे पाठ्य–विषयवस्तु केविधिवत् शिक्षण की पूर्व तैयारी कर सकें अथवा पाठ का समुचित समन्वयन कर सकें। वस्तु विश्लेषण के बारे में प्रायः शिक्षक अपने में सुस्पष्ट और विज्ञ नहीं होते। परिणाम यह होता है कि पूर्वाभ्यास के अभाव में प्रशिक्षु–अध्यापक विश्वासपूर्वक अपने शिक्षण का अभ्यास नहीं कर पाते। उसे वास्तविक शिक्षण–अभ्यास कक्षों में वहाँ के अध्यापकों का यथेष्ट सहयोग नहीं मिल पाता। इसी भाँति अधिकांश शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षु–अध्यापकों के निरीक्षण और मूल्यांकन के लिये किसी स्तरीय मापनी का प्रयोग नहीं किया जाता। उन्हें प्रतिपुष्टि करने के लिये तो अभी तक कोई सर्वमान्य मानक निर्धरित ही नहीं किया गया है। फलतः निरीक्षण कार्य प्रशिक्षु–अध्यापकों की रुचि और इच्छा पर तथा वस्तुनिष्ठता पर निर्भर न होकर, व्यक्तिनिष्ठ रह जाता है। ऐसी दशा में मूल्यांकन में वांछित पारदर्शिता नहीं रह पाती और उनके अपेक्षित शिक्षण व्यवहारों में सुधार नहीं हो पाता है। शिक्षक–शिक्षा और प्रशिक्षु के शिक्षण अभ्यास के बीच वस्तुतः इन दिनों उपयुक्त सामंजस्य नहीं दिखायी देता।

कदाचित् इसी परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रो. के.पी. पाण्डेय जी ने यहप्रस्तावित किया है कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा प्रशिक्षु–अध्यापक में व्यावसायिक ज्ञान में विशेषज्ञता इस प्रकार से विकसित होनी चाहिए कि अर्जित विषय ज्ञान, व्यवहार विधि,संम्प्रेषण कला, सृजनात्मक वृत्ति आदि आयामों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर सके। इसी भाँति बहु संचार प्रौद्योगिकी के शिक्षण और अधिगम के क्षेत्रा में युगीन प्रवृत्तियों को

देखते हुए उनका महत्त्व स्थापित कर सके। प्रशिक्षु अध्यापक अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात् इस दशा में आ जाए कि वे अर्जित ज्ञान, अर्जित सम्प्रेषण कलाओं, उच्चारण की शुद्धता शिक्षण की अभियोग्यता तथा छात्रों के ध्यान को अपनी ओर खींचने की कला में वांछित आधिकारितासे संयोजित हो जाए तथा ऐसी दक्षता से भी मण्डित हो जायें कि वे अधिगम शिक्षण कार्य में नवीनतम प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक व्यावहारिक प्रयोग कर सकें। शिक्षण–अभ्यास का आयाम इस दृष्टि से भी अभावग्रस्त है कि प्रायः प्रशिक्षु अध्यापक अपने अभ्यास पाठों की योजना बनाते समय न तो साफ–साफ तरीके से उनके विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं और न ही उनकी पाठ योजनाएँ शिक्षक–प्रशिक्षुओं द्वारा जाँची जाती है। उनके शिक्षण के आवर्ती निरीक्षण की व्यवस्था भी प्रायः विशेषज्ञ अध्यापकों द्वारा नहीं की जाती है। फल यह होता है कि प्रशिक्षुओं के शिक्षण व्यवहारों में वांछित सुधर नहीं हो पाता।

परिणामतः आज की अध्यापक शिक्षा अनेकानेक शिक्षण अभ्यास संबंधी अभावोंविसंगतियों से जकड़ी है। स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों द्वारा सम्पन्न की जाने वाली अध्यापक शिक्षा और उनके संस्थानों के शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम तो प्रायः मखौल की दशा को पहुँचे नजर आते हैं। इनका निराकरण प्रभावी गुणात्मक सुधर और पुर्नसंयोजन यथाशीघ्र किया जाना चाहिए।

मूल्यांकन संबंधित मुद्दे

'NAAC' ने शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता अनुरक्षण संवर्धन के आशय से पाठ्यक्रम पक्षों पर विचार करते हुए सात परिमापी बिन्दु वांछनीय बनाए हैं –

1. शिक्षण अधिगम
2. मूल्यांकन
3. शोध
4. परामर्श एवं विस्तार
5. अवस्थापन एवं अधिगम संसाधन
6. छात्रा अनुपोषण एवं प्रगति
7. संगठन एवं प्रबन्धन।

अध्यापक शिक्षा संदर्भ में भी यही सात आयामी परिमापी व्यवहार्य समीचीन प्रतीतहोती है। वर्तमान देश प्रदेश के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान और उनकी नियंत्राक NCTE संस्थान भी अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता अनुरक्षण हेतु एतादृशी उपाय कर रही है। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में भी मूल्यांकन आयाम का बड़ा महत्त्व है। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में सैद्धांतिक पाठ्यक्रमांश के मूल्यांकनपूर्वक प्रायोगिक ज्ञान कौशलों की परीक्षा भी समान महत्त्व के साथ की जानी चाहिए। ये दोनों परीक्षाएँ प्रायः संकलनात्मक रूप से सत्र के अन्त में आयोजित की जाती हैं। ये परीक्षाएँ निबन्धत्मक रूप को अधिक महत्त्व देती हैं। यद्यपि परीक्षण व्यवस्थाएँ वस्तुनिष्ठ परीक्षण के लिये जागरूक और प्रयत्नशील अवश्य दिखती हैं पर व्यवहार में इनके परिणाम कम सार्थक दिखते हैं। गहन ज्ञान, अनुप्रयोग क्षमता, संश्लेषण–विश्लेषण, अभियोग्यता एवं अन्यान्य शिक्षण संगठन कुशलताओं का समुचित मापन वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से नहीं हो पा रहा है। ऐसी दशा में उनकी अन्यान्य भावात्मक संयोजन अभियोग्यताओं के मूल्यांकन की बात करना तो कोरी कल्पना ही होगी। प्रचलित मूल्यांकन प्रणाली प्रायः स्मृति एवं पुनः प्रस्तुति की क्षमताओं का ही परीक्षण करती है जो कि अपर्याप्त है।

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमपरक नियोजनात्मक मुद्दे

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 एवं संसोधित शिक्षा नीति 1992 ने 'अध्यापक शिक्षा' को एक निरन्तर प्रक्रिया बताया है, साथ ही इसने इसके सेवापूर्व और सेवाकालीन दोनों घटकों की अपृथकता रेखांकित की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्य पक्षों पर विचार करते हुए अध्यापक शिक्षा संदर्भ में निम्नांकित बिन्दु व्यक्त किए गए हैं–

1. व्यावसायिक दायित्व बोध तथा अध्यापकों की सम्पूर्ण अभियोग्यताएं शिक्षा क्षेत्र में सहनीय हैं।
2. सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा ने गतिशील अभिनव अध्यापन विज्ञान के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं किया है अपितु इसने ह्रासमान प्रवृत्ति तत्वों को दर्शाया है।

3. अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम मुख्यतः सेवापूर्व प्रशिक्षण से जुड़े हैं। उसकी
वस्तुतः कोई सुनियोजित प्रशिक्षण योजनाएँ नहीं हैं और जो वांछित संसाधनों–सुविधओं के अभाव से ग्रसित है।

कहना न होगा '**राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्**' के प्रयासों के बावजूद उक्त कमियों और अभावों से देश की अध्यापक शिक्षा न्यूनाधिक आज भी जकड़ी है जो चिन्तनीय है। सम्प्रति हमारे शिक्षक 21वीं सदी की गतिमान प्रौद्योगिकी के दौर से गुजर रहे हैं। इनअध्यापकों ने यदि आज की प्रवृत्तियों के साथ तादात्म्य न बैठाया तो निश्चय ही वे इससमय के लिये अयोग्य हो जाएँगे। अतएव उन्हें '**इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं सूचनाप्रौद्योगिकी**' की चुनौतियों का मुकाबला करना ही होगा। अतः अध्यापक शिक्षा केपाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों में निश्चित ही परिवर्तन लाया जाना चाहिए। यह भी आवश्यकहै कि अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों की निर्मित में '**जनशक्ति नियोजन**' का उपयुक्त समावेशन किया जाए। अध्यापक शिक्षा को शैक्षिक और सामाजिक व्यवस्था से जुड़करव्यावहारिक होना चाहिए। उपयुक्त तथ्यों के आलोक में यह सुझाव देना उपयुक्त होगा किअध्यापक शिक्षा को नव इलेक्ट्रानिक मीडिया और कंप्यूटर आदि सुलभ नव संसाधनोंसे संबंध्ति किया जाए।

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संबंधी मुद्दे

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्रा में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का अपना महत्त्व है। '**शिक्षाशास्त्र**' विषय में '**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**' के द्वारा कतिपय विश्वविद्यालयों में वर्ष में एक दो बार पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं जिनमें वित्तपोषित विभागों अथवा महाविद्यालयों से प्राध्यापक एवं शिक्षाकर्मी प्रतिभागिता करते हैं किन्तु खेद है कि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी कोई यथेष्ट व्यवस्था अब तक उन महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के लिए नहीं है जो वित्तविहीन विभागों में कार्य करते हैं। ऐसी दशा में ये अध्यापक अपने ज्ञान और प्रविधियों को अद्यतन नहीं कर पाते। निजी स्तर से भी संसाधनाभाव के कारण वे अपने ज्ञानकोश में कुछ नया नहीं जोड़ पाते। इधर चार पाँच वर्षों में स्व–वित्तपोषित इन प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या अप्रत्यासित रूप से बढ़ी है, जहाँ योग्य अध्यापकों की प्रायः बड़ी कमी है। निश्चय ही यह परिस्थिति सोचनीय है। इससे शिक्षण प्रशिक्षण की गुणवत्ता तो घटेगी ही।

आज शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आए हैं। कंप्यूटर, दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट आदि संसाधन अब सुलभ हैं, किन्तु इसका प्रयोग प्रायः हमारे निजी संस्थानों के अध्यापक नहीं कर पाते। यह हानिकारक है। इस प्रकार विशेषकर स्व–वित्तपोषित संस्थानों के प्राध्यापक नवाचारों के ज्ञान और व्यवहार से प्रायः अनभिज्ञ और दूर ही रह जाते हैं। तात्पर्यतः आज का हमारा अध्यापक शिक्षा जगत पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संबंधी अभावों– चुनौतियों से आक्रान्त है जिस पर गम्भीर कार्यवाही नितान्त अपरिहार्य है।

विकास, शोध, मूल्य शिक्षा संबंधी मुद्दे

सस्ते विस्तार की प्रवृत्ति से आक्रान्त होने के कारण आज का सम्पूर्ण अध्यापक शिक्षा तन्त्र सही विकास पथ से दूर है। राष्ट्र और समाज, अध्यापक समुदाय से विकास के नेतृत्व की बड़ी अपेक्षायें रखता है किन्तु हमारी 'अध्यापक शिक्षा' द्वारा प्रसूत ये प्राध्यापक और अध्यापक इस निष्कर्ष पर सही नहीं उतर पा रहे हैं। विस्तार सेवाओं के क्षेत्र में तो ये लगभग शून्य की दशा में हैं।

'**राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्**' गत लगभग 14 वर्षों से अध्यापक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्राों में नवाचारों और शोध को प्रोन्नत करने के प्रयास कर रही है किन्तु कष्ट है कि हमारे अध्यापक शिक्षा संस्थान इन आयामों के क्षेत्र में यथेष्ट प्रगति नहीं कर पा रहे हैं वस्तुतः अध्यापक शिक्षा के क्षेत्रा में व्याप्त समस्या को दूर करने के लिये नवाचारिक प्रयोग एवं क्रियात्मक अनुसंधान का आश्रय आवश्यक है पर इन क्षेत्रों की सक्रियता में आरामप्रिय कार्य संस्कृति बड़ी बाधा है। स्वाभाविक है कि शिक्षक प्रशिक्षक को नवाचारिक प्रयोगों एवं नव अनुसंधान के लिये कार्यकारी ढंग से प्रेरित किया जाए। सभी संबंधित संस्थान विशेषकर स्व–वित्तपोषित शिक्षक शिक्षा संस्थान एतदर्थ वांछित सभी आधुनिकतम संसाधन और सुविधाएँ उन्हें उपलब्ध करायें तभी अभीष्ट की सिद्धि होगी।

अध्यापक–शिक्षा संस्थानों में अभावग्रस्त शिक्षण–प्रशिक्षण अधिगम विधियाँ

वर्तमानकालीन भारत में अध्यापक शिक्षा संस्थानों में अनेक निर्देशों के बावजूद शिक्षक–प्रशिक्षण–अधिगम–विधियों, प्रविधियों में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाया है। वस्तुतः शिक्षण विधियाँ

अध्यापक समुदाय को इस योग्य बनाती हैं कि वे अपनी कक्षाओं में क्यों, कैसे, क्या, कब, कितना आदि प्रश्नों का समाधन ढूँढ़ सकें। इसी भाँति प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों में मुख्यतया विभिन्न अभियोग्यताओं, कौशलों का विकास किया जाता है। अधिगम छात्राों में ज्ञान, क्रिया–कुशलताओं, प्रस्तुति–प्रविधियों, बोध–रसानुभुति आदि का विकास करता है। कतिपय विशिष्ट संस्थानों को छोड़कर, भारत के अधिकांश अध्यापक शिक्षा संस्थानों में इन बातों का आज भी यथेष्ट ध्यान नहीं रखा जाता है। छात्राों को अधिकांशतः व्याख्यान विधि के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। शिक्षण में प्रायः परस्पर संवादी रणनीतियों विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता जबकि संगोष्ठी पद्धति, समूह विमर्श विधि, कार्यशाला विधि, ट्यूटोरियल विधि, अनुरूपी विधि, खेल विधि आदि का प्रयोग भी आवश्यक है। इनका अनुप्रयोग प्रायः अधिक समय और अधिक संस्थानों की अपेक्षा करता है। आज के भारतीय शिक्षक–प्रशिक्षक संस्थान इनमें असमर्थ दिखाई देते हैं जिसका परिणाम गुणवत्ता में बराबर ह्रास होता परिलक्षित होता है। देश के अन्य कई राज्यों में ऐसा ही देखा जा रहा है जो निश्चय ही चिन्तनीय है।

अध्यापक शिक्षा : वर्त्तमान मुद्दे

भारतीय एवं प्रदेशीय उच्च शिक्षा के समक्ष बड़ी चुनौतियाँ, नई नीतियों, रणनीतियों औरक्रान्तिकारी प्रकृति के कार्यक्रमों को बनाने की है। इनमें एक क्षेत्र तो गुणात्मक सुधार काहै, दूसरा समानता लाने का है, तीसरा मूल्यों और दायित्वशीलता के विकास का है, चौथासामाजिक–सांस्कृतिक प्रकृति के समन्वय का है और पाँचवा विकास की प्रक्रिया में सबको जोड़ने का है। इनके निरूपण के लिये श्री जे.पी. नाइक के अग्रांकित त्रिकोण को याद करना होगा, वह त्रिकोण है गुणवत्ता, परिमाण और समानता स्पष्टतः प्रयास सबको गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने का है।प्रत्येक राष्ट्र ने इसके अनुसार बढ़ती प्रतिस्पर्धत्मक प्रवृत्ति को देखते हुए अपनी सूचना अवस्थापना सुविधाएँ बढ़ाई हैं। अपनी शोध एवं नवाचारी प्रक्रियाएं तीव्रतर बनायी हैं। शिक्षा और आजीवन अधिगम को बढ़कर महत्व प्रदान किया है। निश्चय ही इन बातों का प्रदेश की शिक्षक–शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा है

यह पूर्णतः स्वीकार किया गया है कि नव्य ज्ञान का सृजन मुख्यतः शिक्षा व्यवस्था के सशक्तिकरण, देशी शोध के प्रोन्नयन, प्रयोगशालाओं के अभिनवीकरण साथ ही विदेशी स्रोतों से प्राप्त ज्ञान की खुली पहुँच, उनके निवेश और उनकी प्रौद्योगिकी के समुचितअनुप्रयोग पर निर्भर करता है। यह भी सुस्पष्ट है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता ही कल की अर्थव्यवस्था का स्वरूपण करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों की भूमिका बहुआयामी है, सुयोग्य और नवीनतम ज्ञान–विज्ञान से सुसज्जित प्राध्यापक ही इसमें बड़ी भूमिका अदा करेंगे।

सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता आदि नवाग्रही प्रवृत्तियों के प्रचलन का प्रभाव हमारी शिक्षा पर छा रहा है। हमारी अध्यापक–शिक्षा भी इसके अनुरूप स्वरूपित होने को बाध्य है किन्तु उक्त प्रवृत्तियों और कतिपय अन्य परिवर्तित दशाओं के कारण हमारी वर्तमान अध्यापक–शिक्षा अधेलिखित चुनौतियों का सामना कर रही है जो निम्नलिखित है–

1. अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में भारतीय मूल्यादर्शों और सांस्कृतिक प्रतिमानों को फिर से स्थापित किए जाने की चुनौती।
2. युगीन विकेन्द्रीकरण, भूमण्डलीकरण, आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरण की प्रवृत्तियों को समुचित रूप से समंजित करने की चुनौती।
3. बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी को देखते हुए स्वीकार्य संसाधनों को उपलब्ध करने से संबंधित चुनौतियाँ।
4. बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट असंख्य औद्योगीकरण आदि से निपटने की चुनौतियाँ।
5. राष्ट्रीय अस्मिता, संवैधानिक दायित्व, मानवाधिकार संरक्षण, अधिकार कर्त्तव्य बोध, नेतृत्व गुण विकासपरक कुशलता वृद्धि आदि से संबंधित चुनौतियाँ। इस सन्दर्भ में अध्यापक–शिक्षा की भूमिका का निर्धरण।
6. अध्यापक शिक्षा में अभिनव मूल्यों को समाहित करने की चुनौतियाँ।
7. इस परिक्षेत्र में वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष मूल्यांकन मान को अनुरक्षित किये जाने संबंधी चुनौती।
8. आधुनिक उपभोक्तावादी प्रवृत्ति और व्यवहार से निपटने और उन्हें यथापेक्षित नियंत्रित करने की चुनौती।
9. अभिनव शिक्षण पद्धतियों, शिक्षण प्रतिमानों तथा व्यूह रचनाओं के अनुप्रयोग की चुनौती।
10. विशिष्ट शिक्षण कौशलों और क्रियात्मक अनुसंधान कार्य विकास की चुनौती।

11. शैक्षिक तथा शिक्षण प्रौद्योगिकी के प्रचलन एवं मुक्त अधिगम, स्व अधिगम, आत्म–प्रेरित तथा आत्म–निर्देशित अधिगम, व्यवहार में त्वरित परिवर्तनमूलक शिक्षण अधिगम तकनीक आदि के व्यावहारिक समन्वय संबंधी चुनौतियाँ।
12. प्रजातांत्रिक प्रशासन, समशिक्षा अवसर समुपलब्धि तथा समन्वयात्मक प्रबन्धन को व्यावहारिक बनाये जाने से संबंधित चुनौतियाँ।

अध्यापक–शिक्षा जगत की मुद्दे एवं समाधान

सारांशतः आज की भारतीय अध्यापक शिक्षा में उत्कृष्टता, प्रवीणता और समानता केसिद्धांतों की व्यवहार–भूमि में बढ़ी निष्ठा के साथ प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। यह अपेक्षा वस्तुतः नई शिक्षा नीति–1986 के द्वारा उच्च शिक्षा जगत से की गयी है। 'सर्व शिक्षा अभियान' की अनिवार्यता और उसकी साकारता के निहितार्थ से इन दिनों वैसे भी बड़ी संख्या में अध्यापकों की आवश्यकता पड़ी है।इस उद्देश्य की परिपूर्ति के आशय से विश्वविद्यालयों द्वारा एन.सी.टी ई. की अनुमति से अप्रत्याशित संख्या में बी.एड्. कॉलेजों को मान्यता दी गयी है, पर ऐसा करने से निश्चय ही गुणता हासोन्मुख नजर आ रही है। शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध, विस्तार शिक्षा सबसे संबंधित समस्याएँ बढ़ गई हैं। प्रशिक्षण पाने और देने दोनों के व्यय निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। स्व–वित्तपोषित पाठ्क्रम/संस्थान तो बढ़ रहे हैं पर इनकी गुणवत्ता इनका व्यवस्थित संचालन, इनकी वांछित उत्पादकता–प्रतिफल हीन–दशाओं को प्राप्त हो रहा है अतएव सेवा नियोजन अवसरों को दृष्टि में रखते हुए अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन अनुमत किया जाना चाहिए। महिला समानता हेतु भी अध्यापक शिक्षा के ढ़ाँचे को तैयार किया जाना चाहिए। सघन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आयोजना द्वारा श्रेष्ठतम आत्मा वाला शिक्षक समुदाय तैयार किया जाना सर्वथा अभीष्ट है। अतः अभिनव शैक्षिक प्रौद्योगिकी की सहायता लेते हुए सुनियोजित अध्यापक

प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा निष्ठापूर्वक सभी उदीयमान आगत समस्याएँ समाधान की जानी चाहिए। केन्द्र, राज्य सरकारों के साथ निजी क्षेत्र के अग्रणी समृद्ध जन/संस्थाएँ सभी इस फलित अनुष्ठान में भरसक हाथ बंटाएँ। आशा की जानी चाहिए कि हमारी प्रचलित अध्यापक–शिक्षा अवश्य ही क्रमशः वांछित सुधरे पथ पर गतिमान हो सकेगी। उच्च शिक्षा किसी भी राष्ट्र को मुख्यधारा में जोड़ने के लिये मूल आवश्यकता है। इसी के बल पर कोई भी राष्ट्र टिकाऊ ऊर्जा की प्राप्ति कर सकता है और राष्ट्र को प्रगति के शिखर पर पहुँचा सकता है। भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है, इस प्रक्रिया की पूर्णता उच्च शिक्षा ही कर सकती है और इसमें निजी क्षेत्रा बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं।

भारत आज जीवन के सभी क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तनों के पथ पर है। जबसे उदारीकरण, निजीकरण, भूमण्डलीकरण ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में पैर पसारे हैं तब से उच्च शिक्षा के प्रति सभी भारतीयों का आकर्षण बढ़ा है। आज समाज के दलित और वंचित सभी उच्च शिक्षा तक अपनी पहुँच कर रहे हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि निजी उच्च शिक्षा के संस्थान बराबर खुलते जाएँ और जिसमें विश्वस्तरीय गुणत्ता के मानव संसाधित किए जा सकें।

इस परिप्रेक्ष्य में शासन को निजी उद्यमियों के साथ बढ़कर हाथ बंटाना चाहिए। शासन ऐसे कानून बनाए जिससे निजी उद्यमी एक ओर तो प्रोत्साहित होते चलें, दूसरी ओर वे बदले में कुछ लाभ भी संतोष के नाम पर पाते रहें। यह मान्य है कि छात्र–हित, लोकहित, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, पर इसके लिये संयुक्त समन्वित और पहलपूर्ण कदम आगे बढ़ाएँ, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी उद्यमिता में हाथ बटाएँ और शासन इसमें अपना भरपूर सहयोग दे।

आशा की जानी चाहिए कि निजी उच्च शिक्षा का यह परिदृश्य वर्ष 2020 तक भारत
को एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके लिए अध्यापक समाज के सभी लोगों को तथा अध्यापक शिक्षा से सरोकार रखने वाले अध्यापकों को आगे आना होगा, तभी हम अध्यापक शिक्षा की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे और उसकी समस्याओं का समाधन उचित रूप से ढूँढ सकेंगे।

अध्यापक–शिक्षा को सुधारने हेतुसुझाव

1. नव्य प्रौद्योगिकी अपनाई जाए।
2. विशेषज्ञों का सहयोग लिया जाए।

3. नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाए।
4. प्रौद्योगिकी में देश प्रदेश से अनुकूलित परिवर्तन लाया जाए।
5. ज्ञान का देश–कालापेक्षी प्रबंधन किया जाए।
6. प्रशिक्षण को महत्ता दी जाए।
7. रोजगारोन्मुखता को दृष्टिगत रखा जाए।
8. नव्य उद्यमिता विकसित की जाए।
9. दूरसंचार साधनों का अधिकाधिक अनुप्रयोग किया जाए।
10. भूमण्डलीकृत प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखा जाए।
11. विश्वविद्यालय और शिक्षक–शिक्षा के संस्थान अन्य संस्थानों–उद्योगों से जोड़े जाएँ।
12. उत्पादकता और पुरस्कार नीति को सम्मिलित किया जाए।
13. सबका समन्वित निवेश–अनुप्रयोग किया जाए।

इन सुझावों के अमल के लिए देश–प्रदेश की शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था में अनुसारी परिवर्तन लाया जाए। मुखर भूमण्डलीकरण, उदारीकरण, नित नव्य विकसित प्रौद्योगिकी,भौतिक सुख सुविधा उन्मुखी प्रवृत्ति, मुक्त विचरण व्यापार के कारण आज का भारतीय समुदाय भी आन्दोलित है। सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता आदि नवाग्रही प्रवृत्तियों के प्रचलन का प्रभाव हमारी शिक्षा पर छा रहा है। हमारी अध्यापक–शिक्षा भी इसके अनुरूप स्वरूपित होने को बाध्य है किन्तु उक्त प्रवृत्तियों और कतिपय अन्य परिवर्तित दशाओं के कारण हमारी वर्तमान अध्यापक–शिक्षा अधेलिखित चुनौतियों का सामना कर रही है।

संदर्भ ग्रंथ

- एन.सी.ई.आर.टी. (2005), राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005। नई दिल्लीः एन.सी.ई.आर.टी।
- एन.सी.टी.ई. (2009), नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशनः टूअर्डस ए ह्यूमेन एण्ड प्रोफेशनल टीचर, नईदिल्लीः एन.सी.टी.ई.।
- शुक्ल, डॉ आर. एस., 1978, *इमर्जिंग ट्रेड्स इन टीचर एजूकेशन,* इलाहाबाद, चुग पब्लिकेशन्स
- पाण्डेय, रामशकल, 1990, *शैक्षिक प्रगति विशेषांक,* आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर।
- त्यागी, जी. एस. डी., 2002, *आधुनिक शिक्षा का विकास,* आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर
- रस्तोगी डा. कृष्ण गोपाल और मित्तल एम एल, 1993, *भारतीय शिक्षा का विकास और समस्याएँ,* मेरठ, रस्तोगी पब्लिकेशन